

बिहार की विकास प्राथमिकताएँ (Bihar Development Priorities)

1. प्रस्तावना

बिहार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है और इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र तथा तेजी से विकसित हो रहा आधारभूत ढाँचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार के समावेशी और सतत विकास के लिए केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि उत्पादकता, औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढाँचे, शहरीकरण, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एक साथ प्रगति आवश्यक है।

बिहार की विकास रणनीति का मूल उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जिसमें आर्थिक अवसरों का विस्तार हो, मानव पूंजी मजबूत हो, कृषि एवं ग्रामीण आय बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले और क्षेत्रीय असमानताएँ कम हों।

बिहार सरकार की योजना व्यवस्था में भी दीर्घकालिक Vision, Strategy और Work Plan के माध्यम से विकास योजनाओं के समेकन तथा ग्रामीण-शहरी आधारभूत ढाँचे की असमानताओं को कम करने पर बल दिया गया है।

2. बिहार के विकास की प्रमुख प्राथमिकताएँ

बिहार के विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है—

1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का विकास
2. रोजगार एवं कौशल विकास
3. औद्योगिकीकरण और निवेश
4. शिक्षा एवं मानव पूंजी
5. स्वास्थ्य एवं पोषण
6. सड़क, परिवहन और डिजिटल आधारभूत संरचना
7. ऊर्जा एवं विद्युत
8. सिंचाई, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण
9. ग्रामीण विकास
10. शहरीकरण एवं नगरीय आधारभूत संरचना
11. महिला एवं सामाजिक सशक्तीकरण
12. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
13. पर्यटन एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था
14. सुशासन एवं डिजिटल प्रशासन
15. क्षेत्रीय असमानता को कम करना

3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

कृषि क्यों महत्वपूर्ण है?

बिहार की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार में कृषि की केंद्रीय भूमिका है। राज्य के कृषि विभाग के अनुसार कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में बड़ी संख्या में कार्यबल निर्भर है। विभाग कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, फसल विविधीकरण और बेहतर कृषि तकनीक पर जोर देता है।

प्रमुख समस्याएँ

- छोटी एवं सीमांत जोतों की अधिकता
- कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय अंतर
- बाढ़ एवं सूखे का प्रभाव
- सिंचाई की अपर्याप्तता
- कृषि उत्पादों के भंडारण की कमी
- कोल्ड-चेन का सीमित विस्तार
- किसानों को बाजार से बेहतर जोड़ने की आवश्यकता
- कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की कमी
- मूल्य जोखिम
- कृषि में आधुनिक तकनीक का सीमित प्रसार

विकास की प्राथमिकताएँ

(क) सिंचाई का विस्तार

- नहरों का आधुनिकीकरण
- लघु सिंचाई परियोजनाएँ
- भूजल का टिकाऊ उपयोग
- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को बढ़ावा
- वर्षा जल संचयन

(ख) फसल विविधीकरण

धान और गेहूँ के साथ—

- मक्का
- दलहन
- तिलहन
- फल
- सब्जियाँ

- मखाना
- लीची
- शहद
- औषधीय एवं सुगंधित पौधे

जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

(ग) कृषि-आधारित उद्योग

कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर—

उत्पादन → प्रसंस्करण → पैकेजिंग → ब्रांडिंग → विपणन → निर्यात

की पूरी Value Chain विकसित करना आवश्यक है।

(घ) कृषि तकनीक

- ड्रोन
- रिमोट सेंसिंग
- मौसम आधारित सलाह
- डिजिटल मंडी
- मृदा परीक्षण
- स्मार्ट सिंचाई
- कृषि स्टार्टअप
- डिजिटल कृषि सेवाएँ

का विस्तार कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

4. रोजगार एवं कौशल विकास

बिहार की सबसे महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं में रोजगार सृजन शामिल है।

बड़ी युवा आबादी बिहार के लिए एक demographic opportunity है, लेकिन इसके लिए शिक्षा और कौशल को रोजगार की वास्तविक मांग से जोड़ना आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- पर्याप्त गैर-कृषि रोजगार का अभाव
- कुशल श्रमिकों की कमी
- युवाओं का अन्य राज्यों की ओर पलायन
- उद्योगों की सीमित संख्या
- उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता

समाधान

1. Skill Mapping

हर जिले की आर्थिक क्षमता के अनुसार कौशल विकास—

- कृषि
- निर्माण
- IT
- पर्यटन
- स्वास्थ्य
- लॉजिस्टिक्स
- वस्त्र
- खाद्य प्रसंस्करण
- इलेक्ट्रॉनिक्स
- नवीकरणीय ऊर्जा

में किया जाना चाहिए।

2. उद्योग से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण

ITI, Polytechnic, Engineering College और Skill Centres को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना चाहिए।

3. Entrepreneurship

युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि—

Job Seeker + Job Creator

बनाने की दिशा में Startup और Entrepreneurship Ecosystem विकसित करना महत्वपूर्ण है।

5. औद्योगिकीकरण

बिहार के आर्थिक विकास के लिए कृषि के साथ उद्योगों का विस्तार आवश्यक है।

प्राथमिक औद्योगिक क्षेत्र

- खाद्य प्रसंस्करण
- डेयरी
- वस्त्र एवं परिधान
- चमड़ा

- इलेक्ट्रॉनिक्स
- कृषि उपकरण
- निर्माण सामग्री
- फार्मास्यूटिकल्स
- IT/IT-enabled services
- पर्यटन आधारित उद्योग

बिहार में औद्योगिकीकरण की रणनीति

कृषि आधारित उद्योग

जहाँ कृषि उत्पादन अधिक है, वहाँ Processing Units स्थापित की जा सकती हैं।

उदाहरण—

मक्का → पशु आहार/स्टार्च उद्योग

फल-सब्जियाँ → **Processing + Cold Storage**

दूध → **Dairy Processing**

मखाना → **Processing + Packaging + Export**

इस प्रकार कृषि को उद्योग से जोड़कर किसानों की आय और रोजगार दोनों बढ़ाए जा सकते हैं।

औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स

बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए—

- सड़क
- रेल
- नदी परिवहन
- वेयरहाउस
- लॉजिस्टिक्स पार्क
- औद्योगिक क्लस्टर

का विकास निवेश आकर्षित करने में उपयोगी हो सकता है।

6. शिक्षा एवं मानव पूंजी

शिक्षा बिहार के दीर्घकालीन विकास की आधारशिला है।

केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम, शिक्षक प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है।

प्राथमिकताएँ

स्कूल शिक्षा

- आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान
- शिक्षक प्रशिक्षण
- डिजिटल शिक्षा
- विज्ञान एवं गणित की गुणवत्ता
- पुस्तकालय
- प्रयोगशालाएँ
- छात्राओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक विद्यालय

उच्च शिक्षा

- नए डिग्री कॉलेज
- विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता
- शोध एवं नवाचार
- तकनीकी शिक्षा
- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा
- उद्योग-अकादमिक सहयोग

व्यावसायिक शिक्षा

शिक्षा को स्थानीय रोजगार से जोड़ना आवश्यक है।

उदाहरण—

ग्रामीण क्षेत्र → कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण

औद्योगिक क्षेत्र → तकनीकी कौशल

पर्यटन क्षेत्र → Hospitality एवं Tourism Skills

IT क्षेत्र → Coding, AI, Data और Digital Skills

7. स्वास्थ्य एवं पोषण

मानव विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य है।

प्रमुख प्राथमिकताएँ

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना
2. जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना
3. डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता
4. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
5. पोषण
6. टीकाकरण
7. टेलीमेडिसिन
8. मेडिकल कॉलेजों का विस्तार
9. मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ
10. ग्रामीण स्वास्थ्य infrastructure

स्वास्थ्य की नई दिशा

भविष्य की स्वास्थ्य नीति को केवल बीमारी के उपचार के बजाय—

Prevention + Early Detection + Treatment + Rehabilitation

के मॉडल पर आधारित किया जाना चाहिए।

8. सड़क एवं परिवहन आधारभूत संरचना

आर्थिक विकास और परिवहन का सीधा संबंध है।

अच्छी सड़कें—

- बाजार तक पहुँच
- शिक्षा तक पहुँच
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच
- उद्योगों तक कच्चा माल
- कृषि उत्पादों का परिवहन
- रोजगार

को आसान बनाती हैं।

प्राथमिकताएँ

- ग्रामीण सड़क संपर्क
- जिला मुख्यालयों की बेहतर कनेक्टिविटी
- राज्य राजमार्गों का उन्नयन
- पुल एवं पुलिया

- रेलवे कनेक्टिविटी
- सार्वजनिक परिवहन
- माल ढुलाई की सुविधा
- नदी परिवहन

9. ऊर्जा क्षेत्र

विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा औद्योगिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है।

प्राथमिकताएँ

- 24x7 विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति
- कृषि फीडर
- सौर ऊर्जा
- रूफटॉप Solar
- ग्रामीण विद्युतीकरण की गुणवत्ता
- Transmission एवं Distribution सुधार
- ऊर्जा दक्षता

भविष्य में बिहार के लिए Renewable Energy और decentralized solar systems विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

10. सिंचाई, जल प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण

बिहार की विकास नीति में जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव गंभीर चुनौतियाँ पैदा करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति भी देखने को मिलती है।

प्राथमिकताएँ

- बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली
- तटबंधों का रखरखाव
- नदी प्रबंधन
- जल निकासी व्यवस्था
- सिंचाई परियोजनाएँ
- जल संरक्षण
- भूजल recharge
- तालाबों एवं पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन

जल प्रबंधन को केवल बाढ़ नियंत्रण के रूप में नहीं बल्कि—

Flood Management + Irrigation + Groundwater Management + Drinking Water

के एकीकृत दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

11. ग्रामीण विकास

बिहार की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए ग्रामीण विकास राज्य के समग्र विकास का केंद्रीय हिस्सा है।

प्रमुख क्षेत्र

- ग्रामीण सड़क
- पेयजल
- स्वच्छता
- ग्रामीण आवास
- बिजली
- डिजिटल कनेक्टिविटी
- पंचायत स्तर की सेवाएँ
- स्वयं सहायता समूह
- ग्रामीण उद्योग
- कृषि आधारित रोजगार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया मॉडल

कृषि + पशुपालन + मत्स्य पालन + खाद्य प्रसंस्करण + ग्रामीण उद्योग + डिजिटल सेवाएँ

को मिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।

12. पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन

कृषि आय बढ़ाने के लिए allied sectors का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संभावनाएँ

- डेयरी
- पशुपालन
- बकरी पालन
- मुर्गी पालन
- मत्स्य पालन
- मधुमक्खी पालन

इन गतिविधियों से छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है।

डेयरी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के साथ—

Collection → Chilling → Processing → Branding → Marketing

की पूरी श्रृंखला विकसित करना आवश्यक है।

13. महिला सशक्तीकरण

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना बिहार के समावेशी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्राथमिकताएँ

- महिला शिक्षा
- कौशल विकास
- स्वयं सहायता समूह
- महिला उद्यमिता
- बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन
- डिजिटल साक्षरता
- सुरक्षित परिवहन
- मातृ स्वास्थ्य
- महिला कृषि श्रमिकों के लिए समर्थन

महिला SHG को केवल बचत समूह के बजाय—

Enterprise + Production + Marketing + Digital Finance

के मॉडल से जोड़ना अधिक प्रभावी हो सकता है।

14. शहरीकरण

बिहार में शहरीकरण बढ़ने के साथ नगरों पर दबाव भी बढ़ेगा।

प्रमुख शहरी चुनौतियाँ

- यातायात
- जल निकासी
- ठोस कचरा
- पेयजल
- सीवरेज
- प्रदूषण
- अनियोजित विस्तार

- आवास

प्राथमिकताएँ

- Planned Urbanization
- Public Transport
- Sewerage
- Waste Management
- Urban Flood Management
- Affordable Housing
- Green Spaces
- Digital Governance

15. डिजिटल बिहार

Digital Infrastructure आने वाले समय में विकास का multiplier बन सकता है।

प्राथमिकताएँ

- Broadband connectivity
- Digital classrooms
- Telemedicine
- Digital agriculture
- Online government services
- Digital payments
- E-commerce
- Rural BPO
- Cyber security
- AI एवं emerging technologies

डिजिटल तकनीक का उद्देश्य केवल सेवाओं को ऑनलाइन करना नहीं बल्कि नागरिकों की समय, लागत और दूरी को कम करना होना चाहिए।

16. पर्यटन विकास

बिहार ऐतिहासिक, धार्मिक और बौद्ध विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है।

प्रमुख पर्यटन क्षेत्र

- बोधगया

- गया
- नालंदा
- राजगीर
- पावापुरी
- रोहतास
- वैशाली
- पटना
- वाल्मीकिनगर
- मिथिला क्षेत्र
- सीतामढ़ी
- चंपारण
- गंगा आधारित पर्यटन

पर्यटन की विकास रणनीति

केवल monument development के बजाय—

Tourist Site + Connectivity + Hotel + Food + Guide + Local Handicraft + Digital Promotion

का integrated tourism model विकसित किया जाना चाहिए।

इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ सकता है।

17. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य है।

प्रमुख जोखिम

- बाढ़
- सूखा
- अत्यधिक गर्मी
- वज्रपात
- जल संकट
- कृषि उत्पादकता पर प्रभाव
- जैव विविधता में कमी

प्राथमिकताएँ

- Climate-resilient agriculture
- वृक्षारोपण
- Wetland संरक्षण

- जल संरक्षण
- सौर ऊर्जा
- आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली
- resilient infrastructure

18. आपदा प्रबंधन

बिहार में बाढ़, सूखा, वज्रपात तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपदा प्रबंधन विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

चार स्तंभ

Prevention → Preparedness → Response → Recovery

Prevention

जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और सुरक्षित infrastructure।

Preparedness

Early Warning System और स्थानीय प्रशासन की तैयारी।

Response

तेज राहत, बचाव और चिकित्सा व्यवस्था।

Recovery

पुनर्वास तथा livelihood restoration।

19. सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास

विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना आवश्यक है।

प्राथमिकता समूह

- गरीब परिवारसम् का
- महिलाएँ
- बच्चे
- दिव्यांगजन

- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अत्यंत पिछड़े वर्ग
- अल्पसंख्यक समुदाय
- वृद्धजन
- प्रवासी श्रमिक

दृष्टिकोण

Inclusive Growth = Economic Growth + Social Justice + Equal Opportunity

सामाजिक योजनाओं के साथ शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता को जोड़ना दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है।

20. सुशासन

विकास योजनाओं की सफलता केवल बजट आवंटन पर निर्भर नहीं करती। प्रभावी implementation अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Good Governance के प्रमुख तत्व

- Transparency
- Accountability
- Efficiency
- Citizen Participation
- Digital Governance
- Social Audit
- Outcome-based Monitoring

Outcome-based Governance

केवल यह नहीं देखा जाना चाहिए कि—

"कितना पैसा खर्च हुआ?"

बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि—

"उस खर्च से कितना परिणाम प्राप्त हुआ?"

उदाहरण:

विद्यालय बनाए गए → कितने बच्चों की learning outcome में सुधार हुआ?

अस्पताल बनाए गए → स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच कितनी बढ़ी?

सड़क बनी → यात्रा समय कितना कम हुआ?

21. क्षेत्रीय असमानता कम करना

बिहार के सभी जिलों की आर्थिक क्षमता समान नहीं है।

इसलिए एक समान विकास मॉडल के बजाय **District-specific Development Strategy** आवश्यक है।

उदाहरण

कृषि प्रधान जिला → Agro-processing

पर्यटन प्रधान जिला → Tourism Infrastructure

औद्योगिक संभावना वाला जिला → Industrial Cluster

सीमावर्ती क्षेत्र → Border Trade + Connectivity

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र → Resilient Infrastructure + Water Management

इससे स्थानीय संसाधनों और comparative advantage का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

22. बिहार के विकास के लिए प्राथमिकता क्रम

बिहार की विकास रणनीति को व्यापक रूप से निम्नलिखित ढाँचे में समझा जा सकता है—

प्रथम स्तर: Human Capital

शिक्षा + स्वास्थ्य + पोषण + कौशल

द्वितीय स्तर: Productive Economy

कृषि + उद्योग + **MSME** + **Services**

तृतीय स्तर: Infrastructure

सड़क + रेल + बिजली + जल + डिजिटल नेटवर्क

चतुर्थ स्तर: Employment

स्थानीय रोजगार + उद्यमिता + **Skill Development**

पंचम स्तर: Sustainability

Environment + Climate Resilience + Water Management

षष्ठ स्तर: Governance

Transparency + Accountability + Technology

23. बिहार बजट 2026-27 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

बिहार के 2026-27 बजट के Department-wise Annual Scheme Outlay में प्रमुख क्षेत्रों के लिए निम्न आवंटन दर्शाया गया है:

- Rural Development Department — ₹22,392.47 करोड़
- Education Department — ₹18,351.48 करोड़
- Health Department — ₹10,033.27 करोड़
- Urban Development & Housing — ₹9,493.79 करोड़
- Rural Works — ₹8,903.43 करोड़
- Social Welfare — ₹8,379.07 करोड़
- Road Construction — ₹5,869.33 करोड़
- Water Resources — ₹4,836.18 करोड़
- Agriculture — ₹2,525.43 करोड़
- Public Health Engineering — ₹1,999.66 करोड़

कुल Annual Scheme Outlay ₹1,22,155.42 करोड़ दर्शाया गया है।

2026-27 के लिए बजट दस्तावेज में Capital Outlay ₹39,377.06 करोड़ और Fiscal Deficit ₹39,111.80 करोड़ अर्थात् GSDP का 2.99% अनुमानित किया गया है।

इन आँकड़ों से यह समझा जा सकता है कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, ग्रामीण एवं सड़क infrastructure तथा सामाजिक कल्याण बिहार की वर्तमान विकास योजना के प्रमुख expenditure areas में हैं।

24. विकास प्राथमिकताओं का आपसी संबंध

बिहार की समस्याओं को अलग-अलग करके देखने के बजाय इनके बीच संबंध को समझना चाहिए।

उदाहरण:

बेहतर शिक्षा ↓ बेहतर कौशल ↓ बेहतर रोजगार ↓ उच्च आय ↓ अधिक उपभोग एवं निवेश ↓ आर्थिक विकास

इसी प्रकार—

सिंचाई ↓ कृषि उत्पादकता ↓ किसान आय ↓ ग्रामीण मांग ↓ स्थानीय उद्योग ↓ रोजगार

और—

सड़क + बिजली + डिजिटल नेटवर्क ↓ निवेश ↓ उद्योग ↓ रोजगार ↓ राज्य की आय

25. बिहार के विकास की प्रमुख चुनौतियाँ

1. रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन
2. कृषि उत्पादकता बढ़ाना
3. औद्योगिक आधार का विस्तार
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5. स्वास्थ्य infrastructure
6. बाढ़ एवं जल प्रबंधन
7. ग्रामीण-शहरी अंतर
8. क्षेत्रीय असमानता
9. skilled manpower की उपलब्धता
10. निवेश आकर्षित करना
11. बेहतर urban planning
12. पर्यावरणीय स्थिरता
13. सरकारी योजनाओं का प्रभावी implementation

26. आगे की रणनीति

बिहार के लिए विकास की एक प्रभावी रणनीति निम्न प्रकार हो सकती है—

1. Agriculture to Agribusiness

कृषि उत्पादन को processing, branding और export से जोड़ना।

2. Youth to Human Capital

युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और market-oriented skills देना।

3. Migration to Local Opportunity

स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना।

4. Infrastructure to Investment

सड़क, बिजली, जल, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल infrastructure के माध्यम से निवेश का वातावरण तैयार करना।

5. Welfare to Empowerment

कल्याणकारी योजनाओं के साथ कौशल, रोजगार और entrepreneurship को जोड़ना।

6. Flood Risk to Water Management

बाढ़ नियंत्रण के साथ irrigation, drainage और groundwater management को एकीकृत करना।

7. District Planning

प्रत्येक जिले की विशिष्ट आर्थिक क्षमता के आधार पर विकास योजना बनाना।

27. निष्कर्ष

बिहार के विकास की प्राथमिकताएँ बहुआयामी हैं। राज्य के लिए केवल GDP वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। वास्तविक विकास तब माना जाएगा जब आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आय, बुनियादी सुविधाएँ और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो।

बिहार के लिए एक प्रभावी विकास मॉडल को—

"कृषि + उद्योग + मानव पूंजी + आधारभूत संरचना + रोजगार + सुशासन + सामाजिक समावेशन + पर्यावरणीय स्थिरता"

के संयुक्त आधार पर विकसित करना होगा।

विशेष रूप से कृषि को value-added economy से जोड़ना, युवाओं के कौशल एवं रोजगार पर ध्यान देना, औद्योगिकीकरण को गति देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता सुधारना, बाढ़ एवं जल प्रबंधन को मजबूत करना और ग्रामीण-शहरी infrastructure gap कम करना बिहार के दीर्घकालीन विकास के प्रमुख आधार हो सकते हैं।

अतः बिहार के विकास की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तेज आर्थिक वृद्धि के साथ समावेशी, रोजगारपरक, मानव-केंद्रित और सतत विकास है।

राधेश्याम प्रसाद

प्रभारी, जिला अभियोजन पदाधिकारी (सेवानिवृत्त)

